[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

उपलब्ध न होना, इसका वे किस रूप में समर्थन करेंगे ? यू० पी० के चुनाव में कांग्रेस के फंड मे यह रुपया आया। और इसका आज हम यह नतीजा देख रहे है कि इसके प्राइस को डिकंट्रोल किया जा रहा है।

---

## REFERENCE TO NARMADA WATER DISPUTE

**श्री भैरों सिंह शेखावत** (मध्य प्रदेश). सभापति जी, मैं एक प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हू जिस का सम्बन्ध राष्ट्र के आर्थिक विकास पर सीधा आता है। सभापति जी, यह बात सब जानते है कि नर्मदा प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में आज से 20 वर्ष पहले एक रिपोर्ट पेश हुई थी। लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के अन्दर बना कितना भाग कौन सा राज्य उपयोग करेगा,इस प्रश्न को लेकर वाद-विवाद खड़ा हो गया। इस वाद-विवाद के साथ यह प्रश्न भी खड़ा हो गया कि नर्मदा प्रोजेक्ट के वनगांव बांध की ऊंचाई कितनी हो।

सभापति जी, इस प्रश्न को लेकर खोसला कमेटी बिठलाई गई थी और वह इस मामले की टक्नालाजी पर पूरे तरह से गई और उसने अपना एक प्रतिवेदन दिया। प्रतिवेदन देने के बाद उस पर निर्णय देने के लिए एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया। ट्रिब्यूनल के सामने तीनों स्टेटों ने अपने अपने दावे प्रस्तुत किया। इस बीच मामला प्रधान मन्त्री को रेफर कर दिया गया। हम सब लोग उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे अपना इस सम्बन्ध मे निर्णय देगी। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने इस बारे मे कोई निर्णय नही दिया है और इसको फिर से ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया गया है।

सभापति जी, इस योजना को लागू करने के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को 500 करोड़ रुपया सालाना का लाभ हो सकता है। साथ ही हिन्दुस्तान मे बिजली की कमी है, खाद्यान्न की कमी है। बिजली की कमी पूरी समाप्त हो सकती है और खाद्यान्न की कमी भी काफी अंशो तक पूरी की जा सकती है। एक ही पार्टी की सरकार केन्द्र मे है और उसी पार्टी की सरकारे राज्यो मे भी है, फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि तीनो मे इस प्रकार का विवाद चल रहा है और वह तय नहीं हो पा रहा है। मै ऐसा समझता हू कि यह राष्ट्र के साथ ग्रेटेस्ट क्राइम है और इतना बडा हिस्टोरिकल क्राइम है जिसका कि उदाहरण हिन्दुस्तान के बाहर और कही नही मिल सकता। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहा जनता भूखी मर रही है, जहां बेकारी की समस्या है, जहा उद्योग बिजली के अभाव मे पनप नही पा रहे है, जहा हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है भगवान के नाम पर राष्ट्र के हित मे इस विवाद को जल्दी से जल्दी निबटाइए ताकि इस पानी का उपयोग हो सके, बिजली का उत्पादन हो सके और हिन्दुस्तान का औद्योगिक विकास हो सके। यदि इस प्रकार की स्थिति हिन्दुस्तान में बनी रही और निर्णय नहीं हुआ तो और कई प्रकार के जल-वितरण के विवाद हिन्दुस्तान मे खड़े होगें। मैं ऐसा समझता हूं और सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला किया जाय। 1969 मे ट्रिब्यूनल मुकर्रर हुआ था, 72 मे एवार्ड के लिए प्राइम मिनिस्टर को सौंपा गया। 69 का ट्रिब्यूनल आज तक फैसला नही कर पाया और अब फिर आज दूसरे ट्रिब्यूनल को रेफर करेंगे तो यह मामला वर्षों तक चलता रहेगा और देश को बडी भारी हानि होगी। इस प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने इस मामले का उल्लेख किया।

---

## REFERENCE TO FIXATION OF WHEAT PRICE

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आप को स्मरण होगा कि गेहू के भावों से सम्बन्धित एक प्रश्न के उत्तर में सदन के दोनों पक्षों ने चिन्ता व्यक्त की थी और आपने यहा यह आश्वासन भी दिया था कि यदि अवसर मिला तो इस प्रश्न के ऊपर इसी सेशन मे एक चर्चा भी रखेंगे। लेकिन चूकि अन्तिम दिन है और आज की कार्यवाही में उस चर्चा का उल्लेख नही है इसलिए मै आपके माध्यम से चाहूंगा कि कृषि मन्त्री यदि इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे सकें तो दोनों पक्षों को सन्तोष हो सकेगा। स्थिति यह है कि सरकार ने 40 लाख टन का भंडार बनाने का निर्णय किया था और अब तक ढाई लाख टन का भडार भी सरकार इकट्ठा नही कर सकी। उत्तर प्रदेश की, जिस राज्य से मै आता हूं, स्थिति यह है कि मंडियों में गेहूं नही आ रहा है और भावों की स्थिति यह है कि 160 रुपये क्विन्टल से 175 रुपये क्विन्टल का भाव फसल के दिनो मे है। जब फसल समाप्त हो जायेगी, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर मे क्या भाव होगा, आप आसानी से उसका अनुमान लगा सकते है। पजाब की स्थिति के सम्बन्ध मे कृष्णकान्त जी ने उस दिन बताया था कि पंजाब की मंडियो मे भी गेहू नही आ रहा है। सरकार यह प्रयत्न तो कर रही है कि करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा व्यय करके दूसरे देशो से गहू का आयात करें। यदि इतना ही अनुदान देकर किसानों को उचित मूल्य दे दिया जाये और किसानो के घर से वह गेहू बाजारो मे आ जाये तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। मैं यह चाहूगा कि सदन समाप्त होने से पहले आप इस प्रश्न पर कृषि मन्त्री को निर्देश दें कि वे इस सम्बन्ध मे अपनी नीति स्पष्ट करें। आज मैने यह भी पढ़ा है कि पांच प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यो के कृषि मन्त्रियों को केन्द्रीय खाद्य मन्त्री ने यहा बुलाया है। मैं यह चाहूंगा कि आज सदन समाप्त होने से पहले गेहूं के भाव के सम्बन्ध में आप कृषि मन्त्री को वक्तव्य देने का निर्देश अवश्य दें।